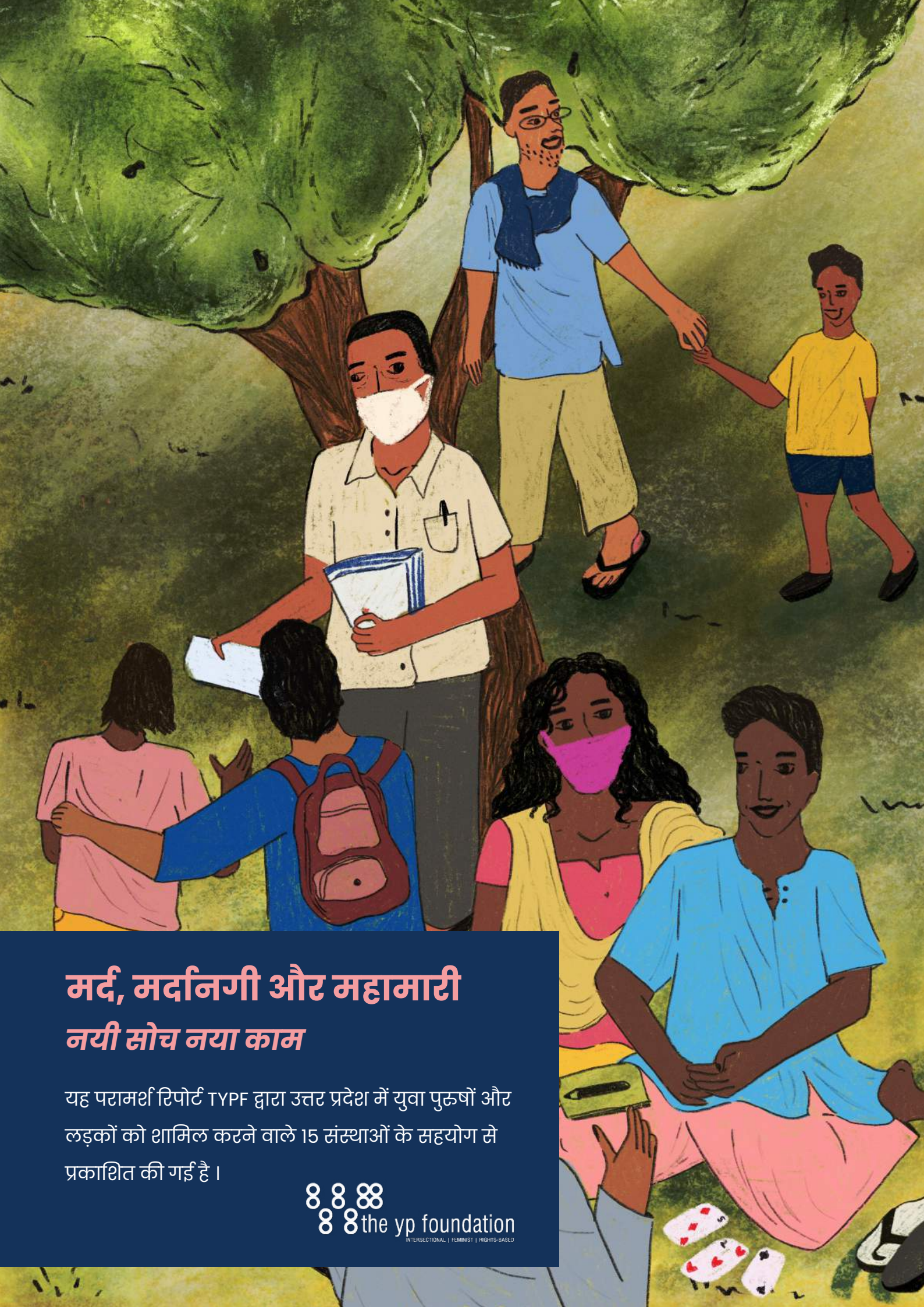

मर्द, मर्दानगी और महामारी

नयी सोच नया काम

यह परामर्श रिपोर्ट TYPF द्वारा उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों को शामिल करने वाले 15 संस्थाओं के सहयोग से प्रकाशित की गई है ।

the yp foundation

INTERSECTIONAL | FEMINIST | RIGHTS-BASED

विषय सूची

परिचय **4**

मर्द, मर्दानगी और महामारी : एक अध्यन्न **7**

पृष्ठभूमि 7

अध्यन्न से प्राप्त नतीजों का सारांश 9

चुनौतियाँ और नयी उभरती आवशयकताएँ 10

नयी सोच, नया काम : आगे की राह **19**

अधिक लचीली, मजबूत और स्थिर प्रोग्रामिग की ओर 19

1. संकट की किसी भी स्थिति में भी कार्यक्रम जारी रखने के लिए समुदायों के साथ गहरे संबंध बनें 19

2. प्रितभागियों की जरूरतों को बेहतर तौर पर समझने के लिए नयी सीख लेने के कार्यक्रम आयोजित हों 21

3. व्यापक बातचीत और अनुभव साझा करने के लिए नेटवर्क का प्रसार हो 23

4. फंडिंग प्राप्त करने के नए और सहयोगी तरीको को खोजना 26

अधिक लचीले, मजबूत और स्थिर निधिकरणों और नीति ढांचों की ओर 28

फंडिंग एजेंसियाँ क्या करें? 28

सरकारें क्या करें? 29

निष्कर्ष **30**

परिचय

भारत में कोविड-19 संक्रमण की पहली लहर का संकट उत्पन्न होने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार नें 22 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी थी और यह लॉकडाउन 18 मई, 2020 तक जारी रहा। लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद शोध अध्यन्नों के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षणों में इन नीतिगत निर्णयों और कोविड महामारी से लड़ने के लिए किए गए प्रयासों से पूरे देश में चल रहे विकास कार्यक्रमों पर पड़ने वाले प्रभावों को अभिलिखित किया गया [1, 2]। विकास कार्यक्रमों में लगे विशेषज्ञों नें अध्यन्न के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने की विवशता, कहीं आने जाने पर लगे प्रतिबंधों, स्कूलों और कालेजों के बंद हो जाने और घर पर रहते हुए काम करने की मजबूरी के कारण विकास कार्यक्रमों के डिज़ाइन और इन्हे पूरा कर परिणाम देने की प्रक्रिया अनेक तरह से प्रभावित हुई। कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न संकट के चलते विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा और प्राथमिकताओं में बहुत से बदलाव आए, काम करने के तरीकों और रणनीतियों में फेरबदल करना पड़ा, परियोजनाओं की समय सीमाएं बिलकुल बदल गईं, संघटन और आउटरीच कार्यक्रम प्रभावित हुए और मोनिटरिंग व आंकलन गतिविधियां भी ख़ासी प्रभावित हुईं। अन्य विकास कार्यक्रमों के अनुभवों के अनुरूप ही टीवाईपीएफ़ के कार्यक्रम और इनका प्रचालन प्रभावित हुआ, जिन समुदायों के बीच कार्यक्रम चल रहे थे उनपर भी इस कोविड संकट का बहुत अधिक असर हुआ। टीवाईपीएफ़ द्वारा फील्ड में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बीच में रोक देना पड़ा, दिल्ली में प्रवासी लोगों के समुदायों के बीच चल रहे प्रयासों को कम देना हमारी विवशता हो गयी क्योंकि इन समुदायों में से अनेक परिवार और किशोर दिल्ली छोड़ कर चले गए थे। मई 2021 के बाद हम फील्ड में चल रहे अपने पाठ्यक्रम में फेरबदल कर पाये और हमनें समुदायों में लोगों से जुड़ाव को अब ऑनलाइन रूप से फोन, व्हाट्सऐप और ज़ूम कॉल के माध्यम से लागू करना शुरू कर दिया। पाठ्यक्रम डिज़ाइन में कुछ फेरबदल कर हमनें इसमें आडिओ विज़ुयल सामग्री भी शामिल कर दी।

---

[1] डेलोइट। (2020, अक्टूबर)। सोशल रिस्पांस टू कोविड-19: रोडमैप टू रिकवरी थ्रू डेवेलपमेंट एंड सीएसआर इनीशिएटिव्स। https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-about-deloitte-covid-19-response-document-indias-development-sector-noexp.pdf

हमारे आउटरीच कार्यक्रमों में फील्ड में काम कर रहे कर्मियों से मिली जानकारी के मुताबिक, लॉकडाउन के कारण समुदायों के लोगों की कठिनाईयाँ बहुत बढ़ने लगी थीं। घरेलू हिंसा होने के अनेक मामले सामने आने लगे थे, कार्यक्रमों में भाग ले रहे प्रतिभागियों से अनेक तरह के उत्पीड़न की घटनाओं की सूचनाएँ मिल रही थी जहां ये लोग अपने लिए कानूनी, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मदद खोज रहे थे - किशोरों और युवा लोगों द्वारा अपने साथियों से मिलने की कोशिश करते हुए समुदाय के लोगों द्वारा सताये जाने और उनके साथ हिंसा किए जाने की घटनाओं में भी बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई थी। बहुत से किशोर और युवा लोगों नें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, विशेष तौर पर सैनीटरी नैपकिन, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, और गर्भसमापन सेवाएँ पाने के लिए संपर्क किया। हमारे कार्यक्रम समन्वयक भी समुदायों में रोजाना आधार पर हो रही समस्याओं से जूझने के परिणामस्वरूप हो रहे तनाव और बर्नआउट से छुटकारा पाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को पाने की आवश्यकता बता रहे थे। फील्ड में कार्यरत समन्वयकों नें समुदायों में कोविड संक्रमण के प्रभाव पर चर्चा करते हुए यह बताया था कि लॉकडाउन को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान समुदायों में जाति आधार पर लोगों के साथ भेदभाव बरता जा रहा था। अप्रैल से जून 2020 के दौरान हमनें खासतौर पर कोविड से जुड़ी समुदायों की जरूरतों का फिर से आकलन किया और हम लॉकडाउन के दौरान समस्या से पीड़ित समुदायों की मदद के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए अलग से संसाधनों की व्यवस्था करने में सफल रहे थे।. [3]

---

[2] डेवेलपमेंट सेक्टर : एडॉप्टिंग टू दि न्यू इकोसिस्टम इन दि कोविड-19 एरा। (2021, मार्च)। वी कम्युनिकेशन। https://we-worldwide-arhxo0vh6d1oh9i0c.stackpathdns.com/media/450023/avian-we-social-impact-whitepaper_digital_03152021.pdf

[3] वाईपी फाउंडेशन। (2020)। यूथ इनसाइट : इनफार्मिंग कोविड-19 रिलीफ एंड रिस्पांस विद यंग पीपुल्स एक्सपीरियंसेज।

कार्यक्रमों में बदलाव करने से जुड़ी इन आरंभिक चुनौतियों, और समुदायों में सामने आ रही कठिनाइयों, विशेषकर घरेलू हिंसा की घटनाओं और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों से जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता में कमी के चलते, हम अपने वर्तमान कार्यक्रमों के डिज़ाइन में बदलाव लाने और कोविड-19 संकट के संदर्भ में युवा पुरुषों और लड़कों के बीच चलाये जा रहे अपने प्रयासों के स्वरूप को बदलने के लिए प्रेरित हुए। उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के बीच पूर्व में काम करते हुए टीवाईपीएफ़ के अनुभवों और शोध से ऐसे कार्यक्रम डिज़ाइन बनाए जाने की ज़रूरत का पता चला था जो जेंडर, यौनिकता, जाति, वर्ग, धर्म और क्षमता के अंतरसंबंधों की वास्तविकता को ध्यान में रखते हों [4] और जिनमें इन लोगों के जीवन की विविध वास्तविकताओं पर ध्यान दिया जा रहा हो।

यही कारण था कि, टीवाईपीएफ़ नें उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के बीच जेंडर, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा जल, स्वच्छता और सफाई (वाश) विषयों पर काम कर रहे 17 विकास उन्मुख संस्थाओंपर कोविड-19 के कारण पड़े प्रभाव का विश्लेषण करने और इसे अभिलिखित करने के लिए और प्राप्त नतीजों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए, आपस में मिलकर और अधिक मजबूती से काम करने के लिए सिफ़ारिशें तैयार करने के उद्देश्य से इस शोध अध्यन्न की शुरूआत की। इस शोध अध्यन्न से प्राप्त नतीजों को विस्तार से एक अलग रिपोर्ट में संकलित किया गया है, और इस लेख में केवल उन परिणामों के सारांश को शामिल किया गया है। इसमें शोध के उपरांत आयोजित परामर्श प्रक्रिया में शामिल 15 संस्थाओं द्वारा 31 अगस्त 2021 को मिलकर तैयार की गयी सिफ़ारिशों को भी शामिल किया गया है।

---

[4] वाईपी फाउंडेशन। (2019)। मर्दों वाली बातें: ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेन मस्क्युलिनिटीज एंड एसआरएचआर।

मर्द, मर्दानगी और महामारी : एक अध्यन्न

पृष्ठभूमि

युवा पुरुषों और लड़कों के बीच चल रहे विकास कार्यक्रमों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्यन्न करने के टीवाईपीएफ़ के इस शोध कार्य में गुणात्मक शोध डिज़ाइन (qualitative research design) को प्रयोग में लाया गया है। हमनें अनेक परिप्रेक्ष्यों में प्रबंधन स्टाफ और फील्ड में काम कर रहे कर्मियों के अनुभवों के आधार पर कोविड-19 के प्रभावों को समझने के लिए ऑनलाइन रूप में विस्तृत इंटरव्यू करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के 17 संस्थाओंसे संपर्क किया। हमारे लिए इन सभी अलग-अलग नज़रियों को जान पाना बहुत महत्व रखता था, क्योंकि लॉक डाउन की पूरी अवधि के दौरान कार्यक्रम प्रतिभागियों के साथ लगातार संपर्क में रहने के कारण जहां एक ओर फील्ड में काम कर रहे लोग, समुदायों में घट रही घटनाओं के बारे में सटीक और पूरी जानकारी दे पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर, इन संस्थाओं के प्रबंधक स्तर के लोगों को अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी थी और वे कोविड के कारण इन कार्यक्रमों में किए जा रहे बदलावों और तब्दीलियों के बारे में पूरी जानकारी रखते थे।

इस अध्यनन में शामिल संस्थाएँ उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनेक विषयों पर काम कर रहीं थीं। हालांकि अध्यनन में प्राप्त सभी जानकारियों को पूरी तरह से समान श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस विश्लेषण से इस तरह के रुझान मिल पाएँ हैं जिनसे कार्यक्रमों को भविष्य में अपने अधिक प्रभावी हस्तक्षेप तैयार करने में सहायता मिलेगी। नीचे दी गई तालिका में इस शोध के लिए इंटरव्यू किए गए संस्थानों के कार्यक्रम संबंधी विविधता का ब्योरा दिया गया है।

तालिका 1: संस्थाओं की कार्यसूची का ब्योरा

संस्था जेंडर, मर्दानगी, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता विषयों पर कार्यरत संस्थाएँ	कार्यक्षेत्र
आँचल	सहारनपुर
एशियन ब्रिज इंडिया (एक साथ)	बनारस
अस्तित्व सामाजिक संस्था	मुजफ्फरनगर
अवध पीपल्स फोरम (एक साथ)	अयोध्या
बदलाव	लखनऊ
ब्रेकथ्रू	समस्त उत्तर प्रदेश में
दिशा फाउंडेशन	जौनपुर
जीपीएस आजमगढ़ (एक साथ)	आजमगढ़
ग्राम्य संस्था	बनारस
एच सी एल फाउंडेशन	नोएडा, लखनऊ
मजदूर खदान यूनियन	मिर्जापुर
प्रोजेक्ट खेल	लखनऊ
पी एस आई	समस्त उत्तर प्रदेश में
सहयोग इंडिया (एक साथ) समर्थ फाउंडेशन की साझेदारी में	हमीरपुर
तरुण चेतना समिति (एक साथ)	प्रतापगढ़
विज्ञान फाउंडेशन	समस्त उत्तर प्रदेश में
वेव फाउंडेशन	समस्त उत्तर प्रदेश में

अध्यन्न से प्राप्त नतीजों का सारांश

कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट और इसके बाद से देश भर लगाए गए लॉकडाउन से जूझने के लिए अधिकांश संस्थाओं नें अनेक तरह के सहायता कार्य करने शुरू कर दिये। इनमें राशन वितरण करने, कोविड-19 के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य कैंप आयोजित करने से लेकर समुदायों में घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं के प्रत्युत्तर में हेल्पलाइन स्थापित करना, समुदाय के लोगों को प्राथमिकी दर्ज करवाने में मदद करना और किसी विवाद कि स्थिति में मध्यस्तता करना शामिल था। सभी संस्थाएं अपने प्रतिभागियों की मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के प्रति भी पूरी तरह से सजग बनी रहीं, और लॉकडाउन के पूरे समय अनेक वर्चुअल माध्यमों से अनेक तरह की गतिविधियां आयोजित कर महामारी से ध्यान हटाने और तनाव दूर करने के प्रयासों में लगी रहीं। बहुत से मामलों में तो, संस्थाओं द्वारा कोविड -19 महामारी के दौरान चलाये गए सहायता कार्यों के कारण उनके अपने लाभार्थी समुदायों से साथ जुड़ाव और भी अधिक प्रगाड़ हो गया।

“कोविड-19 की पहली लहर के दौरान, हमें राशन बांटने का काम शुरू किया। यह एक निर्धन इलाका है और बहुत से लोगों को भोजन की दिक्कत हो रही थी। स्थिति इतनी खराब हो गयी थी, कि अब भी लोग हमारे संस्थान में भोजन सहायता पाने के लिए पहुँचते हैं। राशन बांटने के इस काम के कारण लोग इस क्षेत्र में हमारे द्वारा किए जा रहे काम को जानने लगे”। – फील्ड में कार्यरत कर्मी

चुनौतियाँ और नयी उभरती आवशयकताएँ

कोविड-19 की इस संकट की घड़ी में काम करते हुए संस्थाओं को अपना काम जारी रख पाने में मुख्य रूप से पाँच तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो कार्यक्रमों को ऑफलाइन चलाने की बजाए अब ऑनलाइन माध्यम से चलाना एक विवशता बन गया; दूसरी चुनौती इस लॉकडाउन अवधि में प्रतिभागियों के कार्यक्रमों में भागीदारी को जारी रखने से जुड़ी थी; तीसरे अब समुदायों में नयी तरह की जरूरतें सामने आने लगी थीं जो इन संस्थाओं के कार्यक्रमों की कार्यसूची से बाहर थीं और सबसे बड़ी समस्या इनके सामने यह थी कि कार्यक्रम के तहत इन नयी जरूरतों को किस तरह से पूरी किया जाये; चौथी बड़ी समस्या यह थी कि कार्यक्रम से जुड़े प्रतिभागियों पर कोविड-19 का अलग-अलग तरह से प्रभाव हो रहा था; और पाँचवीं चुनौती कार्यक्रमों के लिए धन आपूर्ति करने और बजट आबंटन की थी।

1. ऑनलाइन तरीके से काम करने की चुनौती

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काम कर रही संस्थाओं के कार्यक्षेत्र वाले समुदायों में लोगों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे, साथ ही गांवों में मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छे से नहीं मिलता था, जिसके कारण इन्हें ऑनलाइन बैठकें करने में बहुत समस्या हुई। इन्हीं कारणों से ऑनलाइन बैठकों और सत्रों में भाग ले रहे प्रतिभागियों की अभिरुचि को भलीभांति समझ पाने में कठिनाई होती रही। इसके अलावा कुछ संस्थाओं नें यह भी बताया कि धन दाता संस्थाओंद्वारा कार्यक्रम की कड़ी समय सीमा निश्चित कर दिये जाने के कारण कई बार तो मॉनिटरिंग और आंकलन गतिविधियां भी ऑनलाइन या फिर टेलीफ़ोन के माध्यम से ही पूरी करनी पड़ीं।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के शहतरि इलाकों में काम कर रहे संस्थानों नें बताया कि उनके समुदायों में टेक्नालजी तक लोगों की पहुँच और उनके पास आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बहुत बेहतर थी। इन संस्थाओं के कार्यक्रमों से जुड़े प्रतिभागी कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से क्रियान्वित्त करने की दिशा में अग्रणी बन कर उभरे। उदाहरण के लिए, दो संस्थाओं नें बताया कि लॉकडाउन के दौरान, अपने तकनीकी रूप से कुशल प्रतिभागियों की सहायता लेते हुए उन्होने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए टिक–टाक प्लैटफ़ार्म का उपयोग करना शुरू कर दिया था। पर्याप्त धन की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में एक से ज़्यादा स्थानों पर काम कर रहे इन संस्थानों नें जानकारी दी कि वे भविष्य में अधिक बेहतर ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के लिए और बड़ी संख्या में विविध प्रकार के प्रतिभागियों तक पहुँच पाने के लिए वैबसाइट और फोन एप्लिकेशन विकसित करने पर भी धन निवेश करने वाले हैं।

2. प्रतिभागियों के कार्यक्रमों में निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करना और कार्यक्रम बीच में छोडने की समस्या का सामना

मजदूर प्रतिभागियों के प्रवास करते रहने की मजबूरी के कारण कोविड-19 से पहले भी संस्थाओं को बीच में ही कार्यक्रम को छोड़ देने की समस्या का सामना करना पड़ता था। लॉकडाउन लगने के बाद उनकी यह समस्या अधिक विकराल रूप लेने लगी क्योंकि इस समय युवा पुरुषों और लड़कों को बहुत ज़्यादा आमदनी बंद हो जाने और काम छूट जाने की समस्या होने लगी। लॉकडाउन शुरू होने के आरंभिक दिनों में शहरों से गाँव आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गयी और विकास कार्यक्रमों में प्रतिभागिता करने वाले युवा अब बड़ी संख्या में उपलब्ध होने लगे लेकिन यह भी अस्थायी व्यवस्था ही बन पायी क्योंकि लोगों की यह बहुतायत बहुत कम समय के लिए ही होती थी। परवासी मजदूर वर्ग भी इन संस्थानों के कार्यक्रमों के साथ जुडने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे क्योंकि उन्हे भी लगता था कि उनकी यह सहभागिता कुछ समय के लिए और अस्थायी ही होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जल्दी ही पटरी पर आ जाएगी और एक बार फिर वे शहर जाकर अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।

“लॉक डाउन के बाद, जब प्रतिभागियों नें बाहर जाना शुरू किया, तब वे लगातार या तो काम कर रहे थे, या फिर काम की तलाश में रहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान आमदनी के नुकसान की भरपाई करने का ही रहता था और वे अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि प्रतिभागी अब बैठकों में भाग लेने के लिए अधिक समय नहीं दे पाते थे। उदाहरण के लिए, हमें रिक्शा चलाने वाले कुछ लोगों को बैठक के लिए बुलाया लेकिन वे बैठक में भाग लेने के लिए इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वे लगातार काम करना चाहते थे।“ – कोऑर्डिनेटर

यहाँ यह जान लेना भी ज़रूरी है कि जहां सभी संस्थाओं नें अपने कार्यक्रमों को बीच में छोडने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी, वहीं पुरुषत्व और जेंडर संबंधी कार्यक्रमों को बीच में छोड़ कर जाने वाले लोगों की संख्या दूसरे विषयों पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों की तुलना में कहीं अधिक थी। देखे गए संस्थानों में इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला तो यह कि पुरुषत्व और जेंडर पर काम कर रहे संस्थानों नें अब अपना काम ऑनलाइन तरीके से चलाना शुरू किया था और जिसमे बार-बार तकनीकी कठिनाईयाँ आती रहती थीं। दूसरे, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बीच में ही रुक जाने के कारण रेफ्रेशर सत्र चलाने की ज़रूरत होती थी और प्रतिभागियों को अक्सर ये सत्र बोर करने वाले लगते थे क्योंकि ये दोबारा चलाये जा रहे होते थे और इस कारण सत्र में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। आखिर में, लोगों के सामने अपनी आजीविका को जारी रखने की प्राथमिकता ज़्यादा थी जिसके कारण ये प्रतिभागी कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने से दूर होते जा रहे थे।

3. कार्यक्रमों की विषयवस्तु में बदलाव लाते हुए नयी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता

विशेष रूप से जल, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों नें अपने कार्यक्रमों की विषयवस्तु को बदलने और अपने लक्षित समूहों में बदलाव लाने में रुचि दर्शाई क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ की कोविड-19 के कारण पड़ने वाले अनेक प्रभावों के चलते कार्यक्रमों में बहुत अधिक बदलाव की ज़रूरत है। इसी तरह, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम कर संस्थाओंनें अपने समुदायों में किशोर उम्र के लड़के व लड़कियों के बीच माहवारी के समय स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भसमापन विषयों सहित, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) पर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। जेंडर मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम चला रही संस्थाओं नें भी, कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के दौरान अपने समुदायों में लोगों और अपने प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहे खराब असर को देखते हुए यह स्वीकार किया कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर भी काम किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन, इस परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी के अभाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर तकनीकी कौशल के अभाव के कारण उन्हें इस बारे में कोई भी कार्यक्रम चला पाने में कठिनाई हो रही थी।

4. उपेक्षित समुदायों पर कोविड-19 का प्रभाव

कार्यक्रमों की विषयवस्तु में बदलाव लाने की ज़रूरत को जान लेने के साथ-साथ, संस्थाओंनें यह भी जान लिया कि कोविड-19 के कारण उनके कार्यक्रमों में भाग ले रहे प्रतिभागियों पर इस महामारी का असर अलग-अलग रूप में हो रहा था और इसका मुख्य कारण प्रतिभागियों की पहचान रहा। प्रवासी श्रमिकों, दलित और मुस्लिम प्रतिभागियों के समूहों में खास तौर पर यह बात महसूस की गयी थी। प्रवासी श्रमिकों के गांवों में मजदूरी करने में हिचकिचाने, दलित श्रमिकों के लिए काम न मिलने और कोविड-19 की पहली लहर के दौरान इस्लाम धर्म के प्रति भय और द्वेष का बढ़ना, ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनसे कोविड-19 के अलग-अलग तरह से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का पता चलता था।

“राशन वितरण के दौरान हमनें देखा कि लोगों की दो पंक्तियाँ बनी हुई थीं और हाशिए पर की गयी जातियों के लोग ऊंची जाति के लोगों से अलग, एक दूसरी पंक्ति बना कर खड़े हुए थे। जब हमनें इस बात पर आपति जताई, तो हमें बताया गया कि इस तरह से भेद या अलगाव करना ज़रूरी था क्योंकि दोनों तरह के लोगों के रहन–सहन में बहुत अंतर था। जाति के आधार पर इस तरह के भेदभाव को बढ़ाव देने हम पूरे लॉक डाउन के दौरान सवाल उठाते रहे थे” – कोऑर्डिनेटर

संस्थाओंऔर संस्थाओं नें यह भी बताया कि कोविड-19 से पहले भी और इस महामारी के दौरान भी, सत्रों में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव को सुलझाने पर अक्सर तनाव उत्पन्न हो जाया करता था। शोध अध्यन्न में भाग ले रहे प्रतिभागी संस्थाओंके अनुसार, आमने-सामने आयोजित होने वाले या फिर इंटरनेट के माध्यम से सत्र आयोजित करने के दौरान एक ही समुदाय के अलग-अलग पहचान वाले वाले लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। इस बारे में संस्थाओं का पूर्व अनुभव यह रहा है कि, सत्रों के दौरान हालात कई बार बहुत विस्फोटक हो जाते थे क्योंकि प्रभावी समुदायों के लोग अक्सर उपेक्षित वर्ग के प्रतिभागियों के साथ गाली-गलौच करने पर आमादा हो उठते थे। ऐसे में अगर सत्र का समन्वय कर रहे लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते तो उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता कि 'वे बाहर से आए लोग' हैं जिन्हें समुदाय की वास्तविक स्थितियों के बारे कुछ नहीं मालूम है। संस्थाओंनें जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी के समय भी जिस तरह से अल्पसंख्यकों और उपेक्षित वर्ग के प्रति जो भेदभाव प्रमुख मीडिया में दिखाई पड़ रहा था, ठीक वैसे ही समुदायों में भी इन वर्गों को कलंकित किए जाते रहने की घटनाएँ बढ़ गयी थीं [5,6]। इस कारण से संस्थाओंको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि इस समस्या का निदान सत्रों में ही इस विषय को उठाकर किया जाना चाहिए। लेकिन जातिगत और धर्म से जुड़े विषयों को उठाने के अपने पहले के अनुभवों को देखते हुए संस्थाओं नें इस विषय पर कोई पहल करने की कोशिश नहीं की।

---

[5] वीरराघव, एस. (2020). नो लौक्डॉन ऑन कास्ट एट्रोसिटीज. दलित्स हूमन राईट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (डीएचआरडीनेट).

[6] वेत्तिकाड, आय. आयम. (2020, May 15). इंडियन मीडिआ अक्यूज़्ड ऑफ़ इस्लामॉफ़ोबिआ फॉर इट्स करोनाविरूस कवरेज. ब्रेकिंग न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ एंड वीडियो फ्रॉम अल जज़ीरा. https://www.aljazeera.com/news/2020/5/15/indian-media-accused-of-islamophobia-for-its-coronavirus-coverage

5. फंडिंग पाने और इसे जारी रखने के लिए धन प्राप्ति के स्रोतों की खोज

केवल एक या दो जिलों में अपने कार्यक्रम चला रहे संस्थाओंको लगता था कि विदेशी मुद्रा नियामक कानून (FCRA) में हुए बदलावों के कारण उनपर इसका प्रतिकूल असर हुआ था। जहां उन्हें लगता था कि इन नए बदलावों के कारण अब वे बैंक में अपना खाता खोल पाएंगे, वहीं वे यह भी सोचते थे कि अब आने वाले समय में उनके सामने फंडिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि अब ग्रांट पाने वाली संस्थाओं द्वारा आगे दूसरे छोटे संस्थाओंको ग्रांट दिये जाने को गैरकानूनी करार दिया गया था और इसीलिए विदेशी अनुदान पाने वाले संस्थाओंसे उन्हें मिलने वाले अनुदान में कमी आने वाली थी। संस्थाओंनें समुदाय में राशन वितरण और दवाइयाँ बांटे जाने पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए अपने कार्यक्रमों के लिए नियत धनराशि से धन उपलब्ध कराये जाने की ज़रूरत के बारे में बताया। कुल मिलाकर, कोविड-19 की महामारी से जूझने के दबाब, FCRA कानून में हुए बदलावों और फंडिंग मिलने की व्यवस्था में एक साथ आए बदलावों को इन संस्थाओंनें अपने सामने एक-साथ उठ खड़ी हुई चुनौतियों के रूप में देखा।

शोध अध्यन्न में संस्थाओंद्वारा व्यक्त विचारों से युवकों और लड़कों के बीच भविष्य में चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में अनेक तरह के प्रश्न हमारे सामने आए, जिन पर विस्तार से चर्चा किया जाना ज़रूरी लगा। जैसे के: **भविष्य में युवकों और लड़कों के बीच चलाये जाने वाले कार्यक्रमों में परस्पर अंतरसंबंध किस तरह के हों? अधिक लचीला कार्यक्रम डिजाइन के लिए किस तरह के नेटवर्क और सहयोग की आवश्यकता है? क्या ऑनलाइन कार्यान्वयन रणनीतियाँ लंबी अवधि में काम कर सकती हैं? क्या उनके जीवन पर COVID-19 के प्रभाव को और अधिक समझने के लिए युवा पुरुषों और लड़कों के साथ प्रत्यक्ष शोध किए जाने की भी ज़रूरत है?** यही सब प्रश्न उस परामर्श बैठक का आधार बने जिसमें शोध अध्यन्न में भाग ले चुके सभी संस्थाओंको शामिल किया गया ताकि विभिन्न विषयों पर पुरुषों और लड़कों के साथ भविष्य की प्रोग्रामिंग के लिए एक सामान्य रोडमैप बनाने के काम को पूरा किया जा सके।

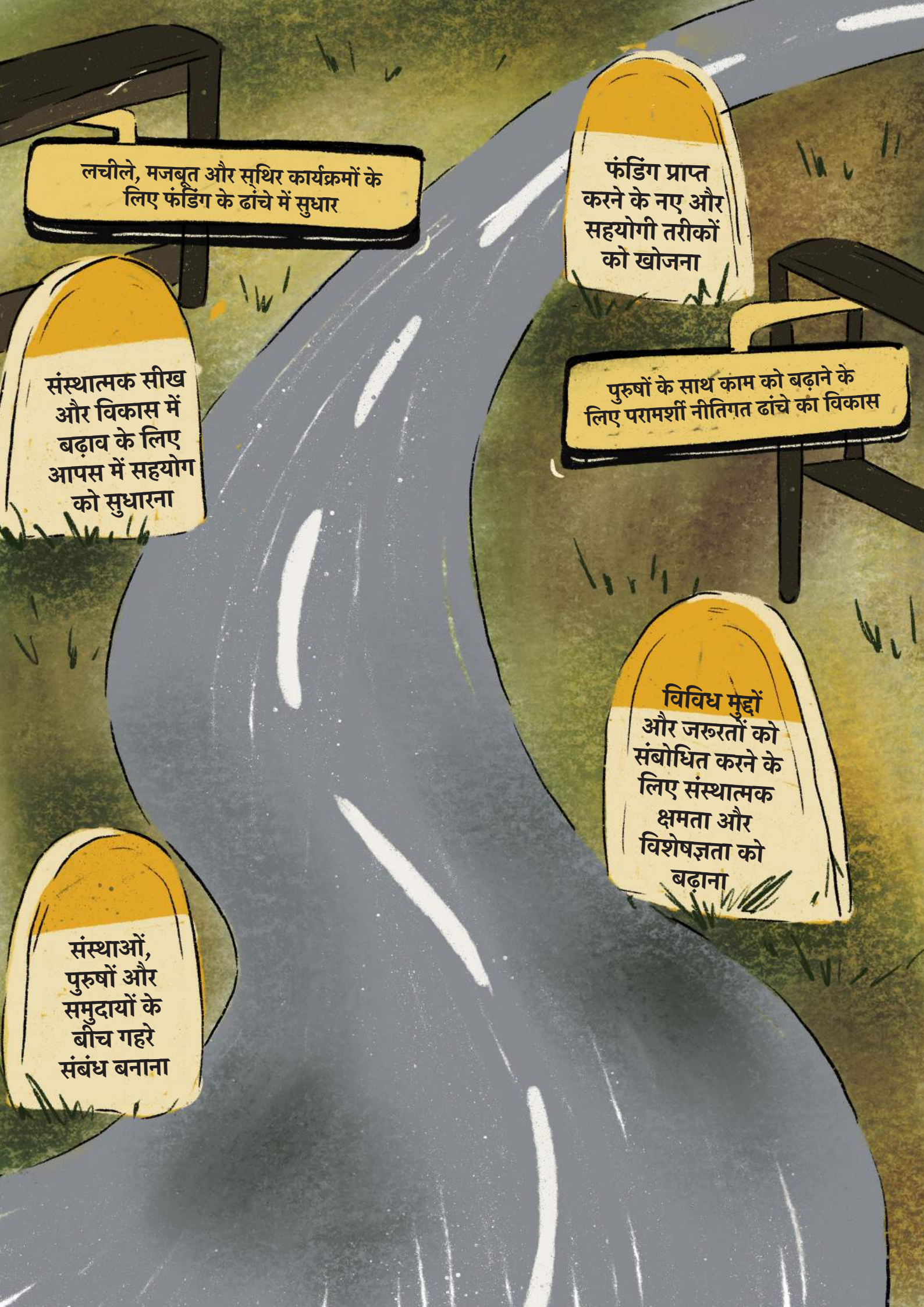
लचीले, मजबूत और स्थिर कार्यक्रमों के लिए फंडिंग के ढांचे में सुधार
फंडिंग प्राप्त करने के नए और सहयोगी तरीकों को खोजना
संस्थात्मक सीख और विकास में बढ़ाव के लिए आपस में सहयोग को सुधारना
पुरुषों के साथ काम को बढ़ाने के लिए परामर्शी नीतिगत ढांचे का विकास
विविध मुद्दों और जरूरतों को संबोधित करने के लिए संस्थात्मक क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाना
संस्थाओं, पुरुषों और समुदायों के बीच गहरे संबंध बनाना

नयी सोच, नया काम : आगे की राह

इस शोध अध्यन्न से मिली जानकारियों से पता चला कि आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेंडर और वाश (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) विषयों पर किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बीच मजबूत जुड़ाव तैयार किए जाने की तुरंत आवश्यकता थी। शोध नतीजों से यह भी पता चला कि अलग-अलग कार्यक्रमों के बीच परस्पर जानकारी, ज्ञान, प्रभावी रणनीतियों और फील्ड में सफल रही उत्तम कार्यप्रणालियों के बारे में नियमित आदान प्रदान संभव बनाने के लिए परस्पर सहभाग के अवसर तैयार किए जाने होंगे। अब जब कि संस्थाओंके बीच परस्पर बातचीत और जुड़ाव बनाने की ज़रूरत प्रमुखता से महसूस की जाने लगी, तब हमें लगा कि शोध से मिली जानकारियों को आधार बनाकर इनका विश्लेषण किया जाये और एक साझा मंच स्थापित करने की दिशा में सबसे पहले मिलकर काम करने पर कुछ सिफ़ारिशें तैयार हों। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में साथ मिलकर काम करने के लिए आगे की रणनीति और योजना तैयार करने हेतु 15 संस्थाओं [7] के 24 प्रतिनिधियों की एक बैठक 31 अगस्त 2021 को आयोजित की गयी।

यह ऑनलाइन रूप से आयोजित आधे दिन का कार्यक्रम था, और इसमें उन सभी संस्थाओंके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिनके साथ पहले आयोजित शोध अध्यन्न के दौरान इंटरव्यू किए गए थे। इस परामर्श बैठक में कई सत्र हुए ताकि युवा पुरुषों और लड़कों के बीच चलाये जा रहे कार्यक्रमों में जुड़ाव पर, कोविड-19 कर कारण कार्यक्रमों में फेरबदल करने की ज़रूरत, सरकार की नयी नीतियों, फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। अगले खंड में इस बैठक के दौरान हुई चर्चा पर और आगे सहभागिता आधार पर किए जाने वाले कामों का ब्योरा विस्तार से दिया गया है।

---

[7] आँचल, एशियन ब्रिज इंडिया, अस्तित्व सामाजिक संस्था, अवध पीपल्स फोरम, ब्रेकथ्रू, दिशा फाउंडेशन, जीपीएस आजमगढ़, ग्राम्य संस्था, एच सी एल फाउंडेशन, मजदूर खदान यूनियन, प्रोजेक्ट खेल, सहयोग इंडिया (समर्थ फाउंडेशन की साझेदारी में), तरुण चेतना समिति, विज्ञान फाउंडेशन, वेव फाउंडेशन।

अधिक लचीली, मजबूत और स्थिर प्रोग्रामिंग की ओर

परामर्श बैठक कर साझा रणनीति तैयार करने की इस प्रक्रिया के अंत में, विभिन्न विषयों पर युवकों और लड़कों के बीच चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में, हमारे सामने आगे की राह इस रूप में प्रशस्त हुई है:

1. संकट की किसी भी स्थिति में भी कार्यक्रम जारी रखने के लिए समुदायों के साथ गहरे संबंध बनें

कोविड की इस महामारी नें हमारे सामने अनेक जटिल मुद्दों, जैसे जाति और सामुदायिक तनाव, आजीविका और जीविकोपार्जन को, उनके विकट रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया और इसके चलते वर्तमान कार्यक्रमों की, ऐसे समय में मदद कर पाने की क्षमता की भी जांच हो पायी। परामर्श चर्चा के दौरान प्रतिभागियों नें विचार किया कि किस तरह से समुदायों के साथ मजबूत संबंध हों तो कैसे भी जटिल मुद्दों को उनके साथ विचार कर सुलझाने की कोशिश की जा सकती है, कैसे किसी आपदा की स्थिति में लोगों की संवेदनशीलटा और आपदा के कारणों को जान कर और परस्पर विश्वास से किसी भी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है।

हमें क्या करना होगा:

- युवकों और लड़कों के जीवन पर कोविड-19 के असर को जानने के लिए **और अधिक शोध हो** और इसमें उन युवकों से सीधे संपर्क कर बातचीत की जाये। विविध पहचान रखने वाले पुरूषों के जीवन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, जेंडर आधारित हिंसा, यौन एवं प्रजनन अधिकार व स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वच्छता आदि अलग-अलग मुद्दों पर काम कर रहे संगठन सहभागी रूप से एक साथ मिलकर भी यह काम कर सकते हैं। इस सहभागी शोध कार्य से मिली जानकारियाँ आगे चलकर अधिक बेहतर और समग्र कार्यक्रम डिज़ाइन तैयार करने का आधार बन सकती हैं।

- **समुदायों के साथ लंबे समय के लिए प्रगाढ़ संबंध बनें** ताकि भविष्य में जाति और धार्मिक तनाव होने पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा संभव हो सके और पहले कोविड-19 के समय जैसी स्थिति उत्पन्न न हो जब समन्वयकों और फील्ड कर्मियों को 'बाहरी लोग' समझा गया था। जैसा कि एक संगठन नें सुझाया कि, समुदाय में लोगों के साथ जेंडर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ही जाति और धर्म से जुड़े मुद्दों पर भी बात की जा सकती है।

- जेंडर, यौनिकता, आजीविका, शिक्षा आदि विषयों पर बेहतर कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए **संस्थाओंद्वारा सामूहिक रूप से लड़कों को फैलोशिप** दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसा करने से, कार्यक्रमों में वॉलंटियर के रूप में काम करने वाले उन लड़कों की भी आर्थिक सहायता हो पाएगी जिन्हें जल्दी आमदनी कमाना शुरू करने के दबाब के चलते कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी जारी रख पाने में कठिनाई होती है।

- **समुदायों में चल रहे युवाओं के नेटवर्कस को मजबूत बनाया जाये** जिससे कि कार्यक्रमों में युवकों और लड़कों की लंबे समय तक भागीदारी सुनिश्चित हो और किसी संकट के समय भी इसमें कोई बाधा न आए। ऐसा करने के लिए सीखने और मनोरंजन की गतिविधियों को एकसाथ मिलाकर आयोजित किया जा सकता है। इनमें खेल-कूद गतिविधियां, फूड फेस्टिवल, नेचर वाक शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की सामान्य गतिविधियों में भाग लेते रहने के अलावा एक साथ मिलकर आपदा सहायता आदि कार्यक्रम करने से लोगों में आपसे सहभाग और सहयोग की भावना पैदा होती है और युवाओं में भी ज़िम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है।

2. प्रतिभागियों की जरूरतों को बेहतर तौर पर समझने के लिए नयी सीख लेने के कार्यक्रम आयोजित हों

“सबसे पहले तो हम उन सभी आईडेंटिटीस या लोगों की उन अलग-अलग पहचान को जान लें जिनके बीच हमें काम करना है। फिर हमें अपनी संस्था में काम कर रहे लोगों को भी इन पहचानो के बारे में पूरी जानकारी देकर उनकी समझ बढ़ानी होगी। हम इन मुद्दों के समाधान तभी खोज पाने में सफल रहेंगे जब हम आपस में मिलकर इन पर काम करें।”

इंटरव्यू किए गए सभी संस्थाओंनें, समुदायों में सामने आ रही नयी जरूरतों को देखते हुए, अपने कार्यक्रम के प्रमुख विषय के अलावा कम से कम एक और विषय के बारे में अपनी जानकारी के स्तर और क्षमता में वृद्धि करने में रुचि दिखाई थी। इन विषयों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव आदि विषय शामिल थे।

हमें क्या करना होगा:

- **संसाधन सामग्री का मिलजुल कर प्रयोग हो** और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बदलाव की कहानियों और इसमें लगे रोल मॉडल लोगों की सेवाएँ एक दूसरे को उपलब्ध करवाएँ ताकि युवकों और लड़कों के बीच विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे नेटवर्क के सभी सदस्यों को अपने काम में मदद मिल सके।

- अलग-अलग संस्थाओंद्वारा विविध भौगोलिक परिस्थितियों और परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे कामों को देखने और समझने के लिए संस्थाओंसे लोग दूसरे संगठन के काम को देखने जाएँ। अलग-अलग संस्थाओं से आने वाले विषय के विशेषज्ञों के साथ साझा सत्र कर **तकनीकी ज्ञान** को साझा करने से भी, अपने काम और कार्यक्रम के अलावा दूसरे संस्थाओंके काम को जानने के लिए स्टाफ के लोगों की क्षमता वृद्धि संभव हो सकती है।

3. व्यापक बातचीत और अनुभव साझा करने के लिए नेटवर्क का प्रसार हो

“इस मंच पर ऐसे अनेक संगठन हैं जो आगे कहीं बडे नेटवर्क और प्लैटफ़ार्म के भी सदस्य हैं। इस तरह से मंच बनाकर संस्थाओंके बीच परस्पर जडाव को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वे मिलकर भेदभाव, रूढिबद्ध विचारों और धारणाओं, जेंडर, जाति और धर्म के मद्दों पर काम कर सकें और इन मद्दों को बडे कैनवास पर सामने ला सकते हैं”।

आज ज़रूरत है कि संस्थाओंके वर्तमान नेटवर्क, खासकर युवा संगठन और नेटवर्क, अपना आधार बढ़ाएँ और अपने कार्यक्षेत्र और समुदाय में और अधिक ऐसे लोगों के संपर्क में आयें जो दूसरों की पसंद नापसंद पर असर डालते हों। ऐसा करने से वे आपदा के समय अपने सदस्य प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाने की चुनौती से बच पाएंगे जिसका सामना हाल ही में उन्होने कोविड-19 महामारी के दौरान किया था, जब बहुत से लोगों को अपनी नौकरी जाने की समस्या का सामना करना पड़ा था और समुदायों की जरूरतों की प्राथमिकताएँ अचानक बदलने लगी थीं।

हमें क्या करना होगा:

- नेटवर्क के वर्तमान सदस्यों द्वारा **स्थानीय मीडिया और प्रिंट मीडिया** से संपर्क साधना उन्हे कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने में सहायक होगा, और इससे पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे संगठन भी भविष्य में होने वाले किसी संकट में वैसी ही कार्ययोजना और चुनौतियों को कम करने की रणनीति अपना पाएंगे। यह विविध संस्थाओंऔर पणधारियों को वर्तमान नेटवर्कस में सदस्यता लेने के लिए भी प्रेरणा साबित हो सकता है।

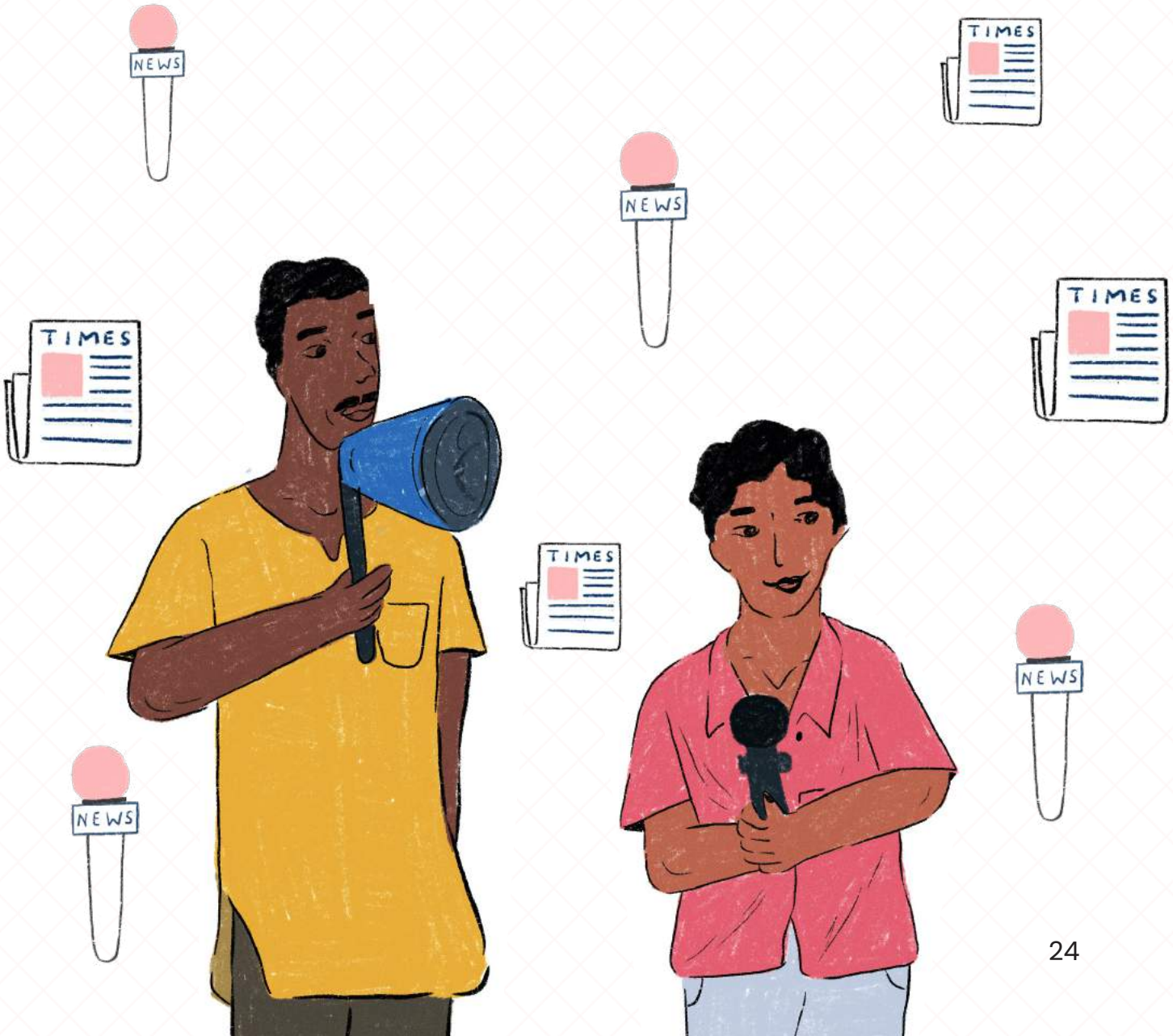

- मर्दानिगी पर युवकों और लड़कों के मन में जानकारी और विचारों को पुष्ट और प्रभावित करने वाले कारकों को पहचाना जाये, जिनहोने विशेष रूप से कोविड-19 के संकट के समय युवकों की सोच को प्रभावित किया – जैसे कि सोशल मीडिया, फिल्में और सिनेमा, इंटरनेट पर अलग-अलग जेंडर के लोगों के साथ हुई बातचीत आदि – और फिर इन सभी माध्यमों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी लंबे समय में अधिक सुलभ और आसान बन पाएगा।

- **युवा संस्थाओंऔर सहभागिताओं को पहचानना** जिससे कि उनके काम के बारे अधिक जाना जाये और अपने नेटवर्क की गतिविधियों में उनका प्रतिनिधित्व और सहभाग बढ़ाया जाये। ऐसा करने से वर्तमान नेटवर्क्स में युवा शक्ति की आवाज़ के अभाव को भी कम किया जा सकता है।

- अल्पसंख्यक और उपेक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व वाले छात्रों और खेल गतिविधियों से जुड़े नेटवर्कों से संपर्क कर **ज़िला स्तर पर सहभागिताएँ** तैयार करना। इस तरह के नेटवर्कों से जुडने का एक तरीका यह हो सकता है कि युवाओं की बहुतायत वाले ज़िला स्तर पर आयोजित होने वाले आयोजनों को साथ लेकर प्लैटफ़ार्म तैयार किए जाएँ।

4. फंडिंग प्राप्त करने के नए और सहयोगी तरीको को खोजना

ऊपर बताए गए सभी कार्यों को करते रहने में सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि फंडिंग कि व्यवस्था कैसे की जाये और लंबे समय तक फंडिंग सुनिश्चित कैसे हो। साथ ही सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुसार काम करते रहना भी एक चुनौती हो सकता है। विकास कार्यों के लिए मिलने वाली अधिकांश फंडिंग इस समय कोविड राहत कार्यों के लिए आबंटित की जा रही है और हाल ही में FCRA कानून में हुए बदलावों के कारण विदेश अनुदान तक सामुदायिक संस्थाओंकी पहुँच सीमित हो गयी है, और इस कारण से कार्यक्रमों के सामने अपने समुदायों के साथ सुचारू ओर प्रभावी ढंग से काम करते रहने की चुनौती उठ खड़ी हुई है। शोध अध्यन्न के दौरान संस्थाओंनें उन उपायों के बारे में भी जानकारी दी जिनके माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कारण उठ रही समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं।

हमें क्या करना होगा:

- FCRA कानून के हाल के बदलावों के बाद, FCRA की अनुमति लिए हुए संस्थाओंद्वारा वित्तपोषित सामुदायिक संस्थाओंको पहले की तरह से फंडिंग पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। इसलिए इन सामुदायिक संस्थाओंको चाहिए कि वे भारतीय फंडिंग एजेंसियों के साथ पैरवी करें और उन्हें युवकों और लड़कों के साथ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के लिए अधिक धन देने के लिए तैयार करें।
- इसके अलावा, अनुदान पाने के लिए केवल फंडिंग एजेंसियों पर आश्रित न रहते हुए, धन के लिए नए स्रोतों और अवसरों को तलाश करने की भी ज़रूरत है। क्राउड़फंडिंग या फिर बड़े उद्यमों की सीएसआर राशि से अनुदान पाने और संस्थाओंके गठबंधन के लिए फंडिंग पाने के लिए साथ मिलकर प्रयास करने की भी ज़रूरत है।
- **कार्यक्रम के प्रस्ताव तैयार करने और संसाधन एकत्रित करने में उन संस्थाओंको सहयोग** दिया जाये जिन्हे इसकी आवश्यकता है ताकि उनकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके और उन्हें भी फंडिंग पाने के अवसर मिलें, खासकर कोविड-19 के कारण फंडिंग पाने में आ रही कठिनाई के परिप्रेक्ष्य में।

अधिक लचीले, मजबूत और स्थिर निधिकरणों और नीति ढांचों की ओर

महामारी के अनुकूल प्रोग्रामेटिक बदलाव करने के इन सुझावों के अलावा, प्रोग्रामर्स ने उस पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की आवश्यकता भी व्यक्त की जिसमें वे काम करते हैं। फंडिंग रणनीतियाँ और नीतिगत ढाँचे उपरोक्त सूचीबद्ध चरणों पर कार्य करने के लिए कार्यक्रमों की क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए, निधिकरण और नीति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कुछ सुझाव नीचे सूचीबद्ध हैं:

फंडिंग एजेंसियाँ क्या करें?

1. संस्थाओंनें बताया कि किसी परियोजना विशेष के आधार पर फंडिंग दिये जाने से समुदायों के साथ लंबे समय तक काम करना जारी रखना कठिन हो जाता है। फील्ड में चल रही अधिकांश परियोजनाओं में केवल समुदाय के साथ कुछ समय तक काम करने के लिए अनुदान दिया जाता है। लंबे समय तक संगठन को धन न देकर केवल अल्पकाल के लिए परियोजना विशेष हेतु धन उपलब्ध करवाने की इस व्यवस्था से, संगठन दीर्घकालिक बदलाव ला पाने में असफल रहते हैं। फंडिंग एजेंसियों को चाहिए कि वे **लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले अनुदान** मंजूर करें, ताकि लंबे समय तक समुदायों के साथ मिलकर काम करने को जारी रखा जा सके।

2. संकट की स्थिति में, फंडिंग एजेंसियों के लिए फील्ड में संस्थाओंके सामने, परियोजना को लागू करने में आने वाली वास्तविक चुनौतियों को समझना और परियोजनाओं की समयसीमा को लचीला रखना बेहद ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, कोविड के दौरान, फील्ड में यहाँ-वहाँ आने जाने पर बहुत सी पाबन्दियाँ लग गयी थीं जिनके कारण क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अगर फंडिंग अजेंसियाँ इस तरह की समस्याओं का संज्ञान लें, तो भविष्य में ऐसे किसी संकट के समय संस्थाओंके सामने परियोजना को समय सीमा का अनुसार पूरा करने का दबाब नहीं रहेगा।

3. शोध में सहभागी संस्थाओंके अनुसार, किसी भी कार्यक्रम में लगे स्टाफ कर्मियों को उचित वेतनमान देना, उस कार्यक्रम की पूरी निष्ठा से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टाफ को वेतन देने से ज़्यादा कार्यक्रम क्रियान्वयन पर अधिक धन खर्च करने का दबाब बना रहता है। फंडिंग एजेंसियों को चाहिए कि वे कार्यक्रम चला रहे प्रबन्धकों के काम और उनकी निष्ठा व उनके द्वारा अनुदान राशि का सही प्रयोग किए जाने पर भरोसा करें। इसके लिए अच्छा होगा कि **फंडिंग की एक सुनियोजित और संतुलित व्यवस्था** अपनाई जाये जिसमें फंडिंग करने वाली एजेंसी और कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर वाले संगठन, दोनों की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाये।

सरकारें क्या करें?

1. प्रतिभागी संस्थाओंका मानना है कि युवकों और लड़कों को जेंडर आधारित हिंसा, असमनाता, परिवार नियोजन आदि विषयों के साथ जोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुझाव दिया गया है कि जहां सरकार और उनके अनेक संबन्धित पक्ष इन विषयों पर नए कार्यक्रम और नीतियाँ बना रहा हैं, उन्हें चाहिए कि वे समुदाय में महिलाओं और पुरुषों, दोनों के सुझाव आमंत्रित करें और इसके लिए बहू-पक्षीय परामर्श बैठकें आयोजित हों।

2. जेंडर आधारित हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और जेंडर असमानता से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए अधिक युवकों और लड़कों को, अतिरिक्त फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के रूप जोड़ा जाये ताकि सरकार के इन कार्यक्रमों में पुरुषों प्रतिभागियों की संख्या बढ़ सके और पुरुषों की सहभागिता भी बढ़े।

निष्कर्ष

अभी इस वर्तमान संकट से जूझते हुए, और भविष्य में ऐसी कि किसी संकट की आशंका को ध्यान में रखते हुए, ऐसी संभावना बनी रहेगी कि इस परियोजना में उठाए गए विषय आगे चलकर समय के साथ-साथ और अधिक गहराते रहेंगे और इनके समाधान खोज पाना अधिक दुष्कर होता जाएगा। हालांकि यह सही है कि आलेख में उठाए गए बहुत से मुद्दे तो इस महामारी से पहले भी मौजूद थे, लेकिन इस संकट के कारण इनकी तीव्रता और जटिलता में बहुत बद्धोतरी हो गयी है। इस दौरान पुरुषों और लड़कों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों में पहले से मौजूद कमियाँ और अधिक बढ़ गयी हैं। हमनें इन कमियों को पहचानने और इनके पीछे के वास्तविक कारणों को जानने की कोशिश की, ताकि हम इन चुनौतियों से जूझ पाने के प्रामाणिक और प्रभावी उपचार खोज पाएँ। यह हमारे लिए न केवल इन मुद्दों और इनसे पार पाने के अपने उन प्रयासों को समझने का अवसर था, जिन्हें हमें इस कोविड-19 संकट के समय अपनाया था, बल्कि यह हमारे लिए उन सब तरीकों पर विचार करना का अवसर भी था जिन्हे प्रयोग में लाकर हम वर्तमान व्यवस्था, आचरण और नेटवर्क्स को एक नया रूप दे पाने की कल्पना कर सकते हैं। हालांकि पुरुषों और लड़कों के बीच चलाये जा रहे कार्यक्रमों की अपनी स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतें होती हैं और ये इन्हीं संदर्भों में कार्य भी करते हैं, फिर भी कार्यक्रम चलाने वालों के कुछ साझा अनुभव ऐसा हैं जिन्हे आधार बना कर हम काम करने के नए तरीके खोज व अपना सकते हैं। साथ मिलकर और सहभागिता करते हुए नयी ऊर्जा से काम करने के दिशा में यह परामर्श हमारा पहला प्रयास था। अब यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि अलग-अलग रहकर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में काम करते रहने से वे व्यवस्थात्मक कमियाँ दूर नहीं हो सकती जिनके कारण जेंडर, यौनिकता, आजीविका, शिक्षा, स्वच्छता, पोषण आदि में असमानताएँ आती और पनपती है। विविध विषयों पर इस तरह से विचार करने और पुरुषों व लड़कों के कार्यक्रमों के नेटवर्क बनाने के प्रयासों की कमी को देखते हुए, हमें पूरी आशा है कि हमारी इस कोशिश से ऐसे अनेक सहभागिताएँ तैयार हो जाएंगी जिनमें पुरुषों और लड़कों के सामने, उनके दैनिक जीवन में आने वाली रोज़मर्रा की चुनौतियों या विशेषाधिकारों पर विचार होगा। आगे की राह, भले ही बहुत अनिश्चित और मुश्किल है, फिर भी इसमें एकमात्र उम्मीद की किरण यही है कि इस काम में लगे संस्थाओं के सुसंगत और एकजुट समुदाय बनें जो लगातार परिवर्तनशील इस संरचना का अनुरूप खुद को ढाल पाने में सफल हों।

क्रेडिट्स

परामर्श समन्वय व दस्तावेज़ीकरण

निहारिका सिंह, सिद्धांत पसरीचा

लेखन कार्य

अवली खरे

सम्पादन व समीक्षा

मानक मटियानी, सागर सचदेवा

रिपोर्ट डिज़ाइन

अंजलि मेनन

द अमेरीकन ज्यूईश वर्ल्ड सर्विस के सहयोग से द वाईपी फ़ाउंडेशन

प्रकाशन : दिसंबर 2021

द वाईपी फाउंडेशन (टीवाईपीएफ) एक युवा विकास संस्था है जो स्वास्थ्य समानता, जेंडर न्याय, यौनिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर युवा लोगों के नारीवादी और अधिकार-आधारित नेतृत्व को बनाता और बढ़ाता है। TYPF सुनिश्चित करता है कि युवाओं के पास उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों और नीतियों के विकास और कार्यान्वियन को सूचित करने और नेतृत्व करने के लिए जानकारी, क्षमता और अवसर हों, और उन्हें सामाजिक परिवर्तन के कुशल और जागरूक नेताओं के रूप में पहचाना जाए।

मर्दों वाली बात कार्यक्रम पुरुषों और लड़कों के साथ काम करता है ताकि जेंडर से जुड़े पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए मर्दानगी पर गहराई से सोच बनाई जा सकें। अनुसंधान और हस्तक्षेप डिजाइनों के माध्यम से, कार्यक्रम युवा पुरुषों और लड़कों के लिए उनके विशेषाधिकारों और कमजोरियों की पारस्परिक प्रकृति पर संवाद करने के लिए इंटरैक्टिव जगह बनाना चाहता है।

टीवाईपीएफ़ की वैबसाइट - theypfoundation.org

टीवाईपीएफ़ के सोशल मीडिया चैनल

@theypfoundation